महन्त राम खिलवाना दास

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(सिविल अपील संख्या 5194/2001)

10 मार्च, 2008

(तरूण चटर्जी एवं हरजीत सिंह बेदी जे.जे.)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - एस. 100 - दूसरी अपील - उच्च न्यायालय ने कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को ठीक से तैयार किए बिना प्रथम अपीलीय अदालत के आदेश को रद्द कर दिया - का औचित्य - माना गया: उचित नहीं - इस प्रकार बनाया गया प्रश्न कानून का पर्याप्त प्रश्न नहीं था, बल्कि केवल तथ्य का प्रश्न था - यह यह अपीलकर्ता की कथित स्वीकारोक्ति पर आधारित था, जिसमें पहले से ही रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य दस्तावेजों और सबूतों की अनदेखी की गई थी, जिसके आधार पर प्रथम अपीलीय अदालत ने अपीलकर्ता के मुकदमे पर फैसला सुनाया था- इसलिए, विधि के सारवान प्रश्न तैयार करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेज दिया गया।

एमआर के पास एक प्रबंधक के रूप में एक मंदिर और कृषि भूमि थी। उन्होंने मंगर के समान उत्तराधिकारी के रूप में अपीलकर्ता को जमीनें वसीयत कर दीं। 1987-88 में कलेक्टर ने जमीनों की नीलामी शुरू की। अपीलकर्ता ने वाद भूमि के संबंध में स्वामित्व की घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया और साथ ही प्रतिवादी-राज्य को उसके आनंद और कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक डिक्री भी दायर की। ट्रायल कोर्ट ने मुकदमा खारिज कर दिया। हालाँकि, अपीलीय

अदालत ने इसकी अनुमति दे दी। दूसरी अपील में उच्च न्यायालय ने कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किया कि क्या अपीलकर्ता-वादी की स्वीकारोक्ति के आलोक में कि उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में नहीं था और उसे 1987 में कलेक्टर द्वारा जबरन बेदखल कर दिया गया था, अदालतों ने नीचे घोषणा और निषेधाज्ञा के लिए डिक्री देने में गलती की गई है। उच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली। इसलिए वर्तमान अपील।

अपील की अनुमति देते हुए और मामले को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहा:

1. दूसरी अपील में, उच्च न्यायालय को निचली अदालतों के निष्कर्षों को अपने स्वयं के निष्कर्षों से प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए, जब तक कि भौतिक साक्ष्य पर विचार का पूर्ण अभाव न हो।

2.1 वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील में विधि के सारवान को ठीक से तैयार नहीं किया ताकि प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले में हस्तक्षेप किया जा सके। उच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया कानून का प्रश्न पूरी तरह से अपीलकर्ता की कथित स्वीकारोक्ति पर आधारित था कि उसके नाम का उल्लेख राजस्व रिकॉर्ड में नहीं था और जिले के कलेक्टर द्वारा उसे जबरन बेदखल कर दिया गया था। साथ ही, यह मानते हुए भी कि अपीलकर्ता की ओर से स्वीकारोक्ति थी, प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले को उलटने से पहले, उच्च न्यायालय को रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य भौतिक साक्ष्यों पर विचार करना चाहिए था, जिस पर पहली अपीलीय अदालत ने आधार बनाया था। इसके निष्कर्ष.

2.2 अधिकारों के रिकॉर्ड में प्रविष्टियाँ केवल यह अनुमान लगाती हैं कि जिस व्यक्ति का नाम अधिकारों के रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, उसके पास मुकदमे की भूमि का कब्जा है, लेकिन इसे रिकॉर्ड पर दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य जोड़कर खंडन किया

जा सकता है। इसलिए, भले ही अपीलकर्ता की यह कथित स्वीकारोक्ति हो कि उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है, यह निर्णायक रूप से साबित नहीं होगा कि अपीलकर्ता मुकदमे की भूमि पर अपना स्वामित्व साबित करने में विफल रहा था, जबकि साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत थे। जहां तक प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता को 1987 में जबरन बेदखल किया गया था, यह एक तथ्य का प्रश्न था, जिसे बिल्कुल भी विधि का प्रश्न नहीं माना जा सकता था। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किया गया विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं था जिसके आधार पर प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले को उलटा किया जा सके।

2.3 प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा निकाले गए तथ्यों के निष्कर्षों से, यह स्पष्ट है कि रिकॉर्ड पर अन्य भौतिक साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शित करते है कि मुकदमे की भूमि से संबंधित अधिकारों के रिकॉर्ड में 8 प्रविष्टियों की धारणा का व्यापक रूप से खंडन किया गया था और निष्कर्ष यह बात पूरी तरह साबित हो गई कि अपीलकर्ता के पास वाद की भूमि का स्वामित्व था। प्रथम अपीलीय अदालत ने इस निष्कर्ष पर पहुंचकर प्रतिवादी के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला था कि प्रतिवादी ने इस आशय का कोई सबूत नहीं दिया था कि खसरा या अन्य सरकारी अभिलेखों में संशोधन करने के लिए अपीलकर्ता या उसके गुरु बाबा राम दास थे। म.प्र. की धारा 115 के तहत कोई नोटिस दिया गया। भूमि राजस्व अधिनियम और तदनुसार, प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा यह माना गया कि अपीलकर्ता उन प्रविष्टियों से बाध्य नहीं था।

2.4 विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न को ठीक से तैयार नहीं किया गया था और इस मामले को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया गया है और दूसरी अपील को विधि के उचित महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करने के लिए उच्च

न्यायालय में प्रेषित किया और उसके बाद अपील पर फैसला किया जाएगा। पहले से ही रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के गुण-दोष के आधार पर।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 5194/2001

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की विशेष अपील संख्या 443/1994 में निर्णय और आदेश दिनांक 17-10-2000 से उत्पन्न।

के. जी. भगत, विनीत भगत, मनोहर सिंह बख्शी, मंजू मल्होत्रा, इहराज जफर और देबाशीष मिश्रा, अपीलार्थी के लिए।

बी. एस. बनथिया (एन.पी.), प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय दिया गया-

तरूण चटर्जी, जे.

1. यह 1994 की दूसरी अपील संख्या 443 में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय जबलपुर के 17 अक्टूबर, 2000 के फैसले और डिक्री के खिलाफ विशेष अनुमति द्वारा एक अपील है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, पन्ना का फैसला और डिक्री, जिन्होंने अपनी बारी में अपीलकर्ता द्वारा दायर घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के मुकदमे को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलकर्ता की अपील की अनुमति को रदद किया था।

2. अपीलकर्ता का मामला यह है कि गढ़ी पड़रिया गांव में 'शाला जानकी रमण मंदिर' के नाम पर एक मंदिर और कृषि भूमि (संक्षेप में "मुकदमा भूमि") जैसा कि वादपत्र के पैराग्राफ 1 में वर्णित है, उनका स्वामित्व था। महंत रामदास, जो अपीलकर्ता के गुरु थे, को उसी के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया। महंत रामदास द्वारा

प्रबंधक के रूप में उत्तराधिकारी बनने के लिए मंदिर और वाद की भूमि अपीलकर्ता को वसीयत कर दी गई। वर्ष 1987-88 में, कलेक्टर पन्ना वाद भूमि की नीलामी शुरू कर दी गई और इसलिए, अपीलकर्ता ने वाद भूमि के संबंध में स्वामित्व की घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया और साथ ही प्रतिवादी को उसके उपभोग और कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री भी दायर की। अपीलकर्ता द्वारा दायर मुकदमा प्रतिवादी ने इस आधार पर विरोध किया कि मंदिर और वाद की भूमि राज्य की संपत्ति थी और महंत रामदास को पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था और उनकी मृत्यु के बाद, अपीलकर्ता को उनके स्थान पर पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था। यह आगे आरोप लगाया गया था जब अपीलकर्ता ने कलेक्टर को त्याग पत्र भेजा, तो उसे स्वीकार कर लिया गया और दूसरा अपीलकर्ता के स्थान पर व्यक्ति को पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था। न तो महंत रामदास और न ही अपीलकर्ता के पास मंदिर या वाद भूमि का स्वामित्व था, जो राज्य की संपत्ति थी और विचाराधीन वसीयत एक मनगढ़ंत दस्तावेज था, जो मंदिर और वाद भूमि को हड़पने के लिए तैयार किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता का मुकदमा खारिज कर दिया। व्यथित महसूस करते हुए, अपीलकर्ता ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, पन्ना के समक्ष अपील की और उसे अनुमति दे दी गई। प्रथम अपीलीय अदालत के इस फैसले के खिलाफ, प्रतिवादी ने दूसरी अपील दायर की, जिसे, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, अनुमति दे दी गई थी। यह उच्च न्यायालय का निर्णय है जो इस अपील में लगाया गया है।

3. दूसरी अपील की अनुमति देते समय, उच्च न्यायालय ने विधि का निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किया था: "क्या वादी की स्वीकारोक्ति के प्रकाश में कि उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड नहीं पाता है और उसे कलेक्टर द्वारा जबरन 1987 में

जबरन बेदखल कर दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उद्घोषणा एवं निषेधाज्ञा की डिक्री देने में त्रुटि की गई है?

4. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने एक त्रुटि की है क्योंकि उसके द्वारा तय किया गया प्रश्न विधि का एक महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं था, बल्कि वास्तव में केवल तथ्य का प्रश्न था और इसलिए, पर्याप्त था। उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए कानून के प्रश्न को कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं माना जा सकता है, जिससे प्रथम अपीलीय अदालत के तर्कसंगत निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सके। यह भी तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने पहले से ही रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य दस्तावेजों और सबूतों की अनदेखी करते हुए अपीलकर्ता की कथित स्वीकारोक्ति पर अपना फैसला सुनाया था, जिसके आधार पर पहली अपीलीय अदालत ने अपीलकर्ता के मुकदमे पर फैसला सुनाया था। अपीलकर्ता के विद्वान वकील की इस दलील का प्रतिवादी के विद्वान वकील ने गंभीरता से विरोध किया, जिन्होंने तर्क दिया कि प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले को उलटने और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बहाल करने में उच्च न्यायालय पूरी तरह से उचित था।

5. दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुना और उच्च न्यायालय के साथ-साथ अधीनस्थ की अदालत के फैसले और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्रियों की जांच करने के बाद, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को ठीक से तैयार नहीं किया है। दूसरी अपील में ताकि प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले में हस्तक्षेप किया जा सके। हमारी राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया कानून का प्रश्न पूरी तरह से अपीलकर्ता की कथित स्वीकारोक्ति पर आधारित था कि उसके नाम का उल्लेख राजस्व रिकॉर्ड में नहीं था और उसे जिले के कलेक्टर द्वारा जबरन बेदखल कर दिया गया था। साथ ही, यह मानते हुए भी कि अपीलकर्ता की ओर से स्वीकारोक्ति

थी, प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले को उलटने से पहले, उच्च न्यायालय को रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य भौतिक साक्ष्यों पर विचार करना चाहिए था, जिस पर पहली अपीलीय अदालत ने आधार बनाया था। इसके निष्कर्ष. यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि अधिकारों के रिकॉर्ड में प्रविष्टियाँ कब्जे का अनुमान लगाती हैं और जब पक्ष सबूत पेश करते हैं, तो अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंच सकती है कि अधिकारों के रिकॉर्ड में प्रविष्टियाँ मुकदमे की भूमि के संबंध में हैं। ग़लत थे. इसलिए, भले ही अपीलकर्ता की यह कथित स्वीकारोक्ति हो कि उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है, यह निर्णायक रूप से साबित नहीं होगा कि अपीलकर्ता मुकदमे की भूमि पर अपना स्वामित्व साबित करने में विफल रहा था, जबकि रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत थे। ऐसे शीर्षक को सिद्ध करें. जहां तक इस सवाल का सवाल है कि क्या अपीलकर्ता को 1987 में जबरन बेदखल किया गया था, यह एक तथ्य का सवाल था, जिसे बिल्कुल भी कानून का एक बड़ा सवाल नहीं माना जा सकता था। इसलिए, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किया गया विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं था जिसके आधार पर प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले को उलटा किया जा सके।

6. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि दूसरी अपील में, उच्च न्यायालय को निचली अदालतों के निष्कर्षों को अपने स्वयं के निष्कर्षों से प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए, जब तक कि भौतिक साक्ष्य पर विचार का पूर्ण अभाव न हो। 'कोंडीबा दगडु कदम बनाम सावित्री बाई सोपान गुजर (1999) 3 एससीसी 722' इसके अलावा, उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि व्यावहारिक रूप से, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की कथित स्वीकारोक्ति पर प्रथम अपीलीय अदालत के निष्कर्षों को इस हद तक पलट दिया था कि उसके नाम का उल्लेख नहीं किया गया था। वाद भूमि के संबंध में अधिकारों का प्रासंगिक रिकॉर्ड। हमारे विचार में, जैसा कि यहां पहले उल्लेख किया गया है, भले ही अपीलकर्ता द्वारा ऐसी स्वीकारोक्ति की गई हो,

तब भी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि अपीलकर्ता के पास वाद भूमि का कोई स्वामित्व नहीं था, जबकि, माना जाता है कि, अपीलकर्ता ने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर अपने वाद को प्रमाणित कर दिया था। अदालतों के समक्ष रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री-वृत्तचित्र और यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि अधिकारों के रिकॉर्ड में प्रविष्टियाँ केवल यह अनुमान लगाती हैं कि जिस व्यक्ति का नाम अधिकारों के रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, उसके पास मुकदमे की भूमि का कब्जा है, लेकिन इसे साक्ष्य-वृत्तचित्र या दस्तावेज जोड़कर खंडन किया जा सकता है। रिकॉर्ड पर। वर्तमान मामले में, जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि उच्च न्यायालय ने, केवल अपीलकर्ता की कथित स्वीकारोक्ति पर भरोसा करते हुए, तथ्य के प्रश्न पर प्रथम अपीलीय अदालत के निष्कर्षों को उलट दिया था। हालाँकि, प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा निकाले गए तथ्य के निष्कर्षों से, यह स्पष्ट है कि रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य भौतिक साक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखाएंगे कि मुकदमे की भूमि से संबंधित अधिकारों के रिकॉर्ड में प्रविष्टियों की धारणा का पूरी तरह से खंडन किया गया था और निष्कर्ष यह बात पूरी तरह साबित हो गई कि अपीलकर्ता के पास वाद की भूमि का स्वामित्व था। प्रथम अपीलीय अदालत ने प्रतिवादी के खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला था, जिसमें पाया गया था कि प्रतिवादी ने इस आशय का कोई सबूत नहीं दिया था कि खसरा या अन्य सरकारी रिकॉर्ड में संशोधन करने के लिए अपीलकर्ता या उसके गुरु बाबा राम दास थे। म.प्र. की धारा 115 के तहत कोई नोटिस दिया गया। भूमि राजस्व अधिनियम और तदनुसार, यह प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा निर्धारित किया कि हमारे समक्ष अपीलकर्ता उन प्रविष्टियों के लिए बाध्य नहीं था। जहां तक मुकदमे की जमीनों पर कब्जे का सवाल है, प्रथम अपीलीय अदालत, जो तथ्य की अंतिम अदालत थी, ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले थे: -

"अपीलकर्ताओं के पीडब्ल्यू के अलावा, अंगद प्रसाद पांडा ई (आरडब्ल्यू -3) और के.एल. पैक्रे (आरडब्ल्यू -4) ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि अपीलकर्ता मंदिर का पुजारी था और आज तक, वह भूमि पर खेती कर रहा था। पिछले 2 साल पहले तक। अपीलकर्ता ने अपने बयान के पैरा नंबर 3 में कहा है कि वह 30 एकड़ भूमि पर खेती कर रहा है और शेष गायों और बछड़ों के लिए छोड़ दी गई है। प्रतिवादी ने नीलामी खरीदार आशा राम पुजारी की जांच नहीं की है। उनके बयान के अभाव में, बचाव निराधार और इसके विपरीत हो जाता है, धारणा यह है कि अपीलकर्ता अभी भी मंदिर शाला जी जानकी रमन की पूजा कर रहा है और उसकी जमीन पर उसका कब्जा है।"

जैसा भी हो, उपरोक्त पहलू पर सकारात्मक निष्कर्ष पर आए बिना, हमारा विचार है कि कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न ठीक से तैयार नहीं किया गया था और इस मामले को ध्यान में रखते हुए, अपील की अनुमति दी जानी चाहिए और निर्णय सुनाया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया और दूसरी अपील को कानून का उचित महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने के लिए उच्च न्यायालय में भेज दिया गया और इस तरह के प्रश्न तैयार करने के बाद, पहले से ही रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपील पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ें। इस निर्णय में हमारी जो भी टिप्पणियाँ हैं, उन्हें अस्थायी माना जाएगा और उच्च न्यायालय कानून का उचित महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने के बाद दूसरी अपील पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

7. उपरोक्त कारणों से, ऊपर बताई गई सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है। हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि इस आदेश की प्रति की आपूर्ति की तारीख

से 6 महीने की अवधि के भीतर दूसरी अपील का निपटारा किया जाए। लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अरविन्द कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।